"वह रास्ता जो एड्स को ख़त्म करता है": रिपोर्ट

संदर्भ: एचआईवी - एड्स मामलों पर संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (UNAIDS) की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक एड्स का ख़ात्मा करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग मौजूद है, जिसके लिए मज़बूत राजनैतिक नेतृत्व के साथ विज्ञान को अपनाने, विषमताओं का मुक़ाबला करने और सतत निवेश सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता होगी।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

एड्स का प्रभाव: 2022 में, एड्स से हर मिनट एक जान गई है , दुनिया भर में लगभग 9.2 मिलियन लोग एचआईवी उपचार तक पहुंचने में असमर्थ हैं।

उपचार की स्थिति: लगभग 29.8 मिलियन लोग एचआईवी उपचार प्राप्त कर रहे हैं, और 2025 तक 35 मिलियन लोगों को उपचार उपलब्ध करने का लक्ष्य सफलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है।

लिंग असमानताएँ: एचआईवी से पीड़ित पुरुषों में महिलाओं की तुलना में उपचार दर कम है।

बच्चे प्रभावित: 2010 के बाद से बच्चों में एड्स से संबंधित मौतों में 64% की कमी के बावजूद, 2022 में लगभग 84,000 बच्चों ने एचआईवी से अपनी जान गंवाई है।

रिपोर्ट में सुझाव:

कलंक-मुक्त स्वास्थ्य सेवा: स्वास्थ्य सुविधाओं में कलंक को खत्म करना और अविश्वसनीय कानूनों और प्रथाओं को हटाना महत्वपूर्ण है।

महिला-अनुकूल रोकथाम: महिला-अनुकूल बायोमेडिकल रोकथाम उपकरणों तक आसान पहुंच यौन सक्रिय लड़कियों और महिलाओं में एचआईवी के जोखिम को कम कर सकती है।

फंडिंग और रोकथाम: फंडिंग में अंतर को कम करने से, एचआईवी की घटनाओं में और गिरावट आ सकती है।

भारत के बारे में :

- भारत के 2022 एचआईवी आँकड़ों के मुताबिक़, देश में अनुमानित 24 लाख 70 हज़ार लोग एचआईवी से पीड़ित, जिनमें वयस्कों के बीच एचआईवी का प्रसार 0.2% है।
- वर्ष 2022 में नए एचआईवी संक्रमण मामलों की संख्या अनुमानित 66 हज़ार थी, हालाँकि 2010 के बाद से नए संक्रमणों की दर में 42% से थोड़ी अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जो वैश्विक औसत 38% से थोड़ी ज़्यादा है. 2010 के बाद से एड्स के कारण कुल मृत्यु दर में लगभग 77% की गिरावट आई है।
- यूएनएड्स में एशिया प्रशान्त, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के क्षेत्रीय निदेशक, एमॉन मर्फ़ी का कहना है कि भारत सरकार ने एड्स प्रतिक्रिया में राष्ट्रीय स्वामित्व और नेतृत्व का प्रदर्शन किया है।
- भारत में 2022 में एचआईवी से पीड़ित 79% लोगों को अपनी स्थिति की जानकारी है. जो लोग अपनी एचआईवी स्थिति जानते हैं, उनमें से एचआईवी से पीड़ित 86% लोग एंटीरैट्रोवाइरल उपचार करा रहे हैं।
- जिन लोगों का इलाज चल रहा है और वायरल लोड के लिए परीक्षण किया गया है, उनमें से 93% पीड़ितों का वायरल दबाने में सफलता प्राप्त हुई है. देश के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता -, एचआईवी से पीड़ित उन लोगों तक पहुँचना है जो अपनी स्थिति के बारे में तो जानते हैं लेकिन इलाज के बारे में नहीं नही जानते हैं।
- भारत, प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (पीआरईपी) और वर्चुअल हस्तक्षेप जैसे नवीन समाधानों का लाभ भी उठा रहा हैं; साथ ही, सेवाओं तक पहुँच बनाना और अधिक सक्षम वातावरण बनाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त नीति सुधार भी लागू कर रहा है. लेकिन कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिए नए व प्रभावी नेतृत्व की ज़रूरत है।

यूएनएड्स के बारे में:

संयुक्त कार्यक्रम: UNAIDS संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सहप्रायोजकों के समन्वय से 11 वें सतत विकास लक्ष्य के हिस्से के रूप में 2030 तक एड्स को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करता है।

मिशन: यूएनएड्स का लक्ष्य एचआईवी की रोकथाम, उपचार, देखभाल और सहायता तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है।

नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व: यूएनएड्स संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिए एक मॉडल है और इसके शासी निकाय में नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करता है।

एचआईवी और एड्स अवलोकन:

एचआईवी क्या है?

एचआईवी (ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस) शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे यह संक्रमण और बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।

एड्स क्या है?

एड्स एचआईवी संक्रमण का अंतिम चरण है इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है।

उपचार: एचआईवी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रभावी एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) वायरल के प्रभाव को कम करने में मदद करती है और एड्स को बढ़ने से रोकती है।

भारत में प्रयास: राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) भारत में एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों का नेतृत्व करता है, जिसका लक्ष्य 2030 तक एड्स को समाप्त करना है।

राष्ट्रीय एड्स समिति: पहला एड्स मामला सामने आने के बाद 1986 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में इसका गठन किया गया।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम: यह 1992 में शुरू किया गया था, तथा कार्यक्रम को लागू करने के लिए NACO का गठन किया गया था।

95-95-95 रणनीति: 2025 तक 95% परीक्षण, उपचार और वायरल रोक थाम दर का लक्ष्य तथा पिछली 90-90-90 रणनीति को सफल बनाना।

भारत-यूएई संबंध

संदर्भ: हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने पिछले आठ वर्षों के भीतर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अपनी पांचवीं यात्रा संपन्न की।

यात्रा के परिणाम:

समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर: सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं (INR-AED) के उपयोग को बढ़ावा देने, भुगतान और संदेश प्रणालियों को जोड़ने और अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,दिल्ली की स्थापना के लिए विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

ऊर्जा क्षेत्र: हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और ग्रिड कनेक्टिविटी में सहयोग; भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम में निवेश में वृद्धि पर सहमती व्यक्त की गई।

जलवायु परिवर्तन: भारत की G20 और संयुक्त अरब अमीरात की COP28 की अध्यक्षता के दौरान जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर संयुक्त कार्य; COP28 को सफल बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

भारतीय प्रवासी: द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने वाले देश में भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए यूएई की सराहना की गई।

द्विपक्षीय व्यापार: आर्थिक साझेदारी 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जिसका लक्ष्य दिल्ली में जी20 बैठक से पहले 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुचना है।

सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राएँ:

समझौता: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सीमा पार लेनदेन में रुपये और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम (एईडी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

तंत्र: इसके लिए घरेलू मुद्राओं में चालान और भुगतान को सक्षम करने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (एलसीएसएस), एक आईएनआर-एईडी विदेशी मुद्रा बाजार विकसित किया जायेगा।

महत्व: संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों से निवेश, प्रेषण को सुविधाजनक बनाना और लेनदेन लागत और प्रेषण के लिए समय को कम किया जा सकेगा।

कच्चे तेल का भुगतान: भारत संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल और अन्य आयात के लिए तंत्र का उपयोग कर सकता है, जो वर्तमान में अमेरिकी डॉलर में किया जाता है।

भारत-यूएई द्विपक्षीय संबंधों पर संक्षिप्त जानकारी:

राजनयिक संबंध: 1972 में स्थापित।

साझा दृष्टिकोण: भारत का विजन 2047 और यूएई की शताब्दी योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण में समानताएं पैदा करती है, जिससे आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं।

व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए): द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया गया, जिससे यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।

एनआरआई प्रेषण: संयुक्त अरब अमीरात में स्थित भारतीय समुदाय सालाना प्रेषण में 17.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान देता है।
ऊर्जा सुरक्षा: एक ऊर्जा निर्यातक के रूप में यूएई की विश्वसनीयता भारत के औद्योगिक और विनिर्माण विकास की पूरक है।
प्रौद्योगिकी साझेदारी: हस्ताक्षरित डिजिटल नवाचार, प्रौद्योगिकी साझेदारी और अंतरिक्ष मिशन पर सहयोग।
रणनीतिक अभिसरण: अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व, आतंकवाद और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जैसे रणनीतिक मुद्दों पर साझा विचार प्रकट किया गया है।
लघुपक्षीय समूह: भारत-इजरायल-अमेरिका-यूएई (I2U2) और भारत-यूएई-फ्रांस समुद्री त्रिपक्षीय समूह का गठन किया गया है।

सांख्यिकी पर स्थायी समिति (एससीओएस)

संदर्भ: हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के सभी डेटा की समीक्षा के लिए एक नया पैनल स्थापित किया है।

एससीओएस के बारे में:
जनादेश विस्तार: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के तहत सभी सर्वेक्षणों की समीक्षा करने के लिए व्यापक जनादेश के साथ आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति (एससीईएस) को सांख्यिकी पर स्थायी समिति (एससीओएस) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

अध्यक्ष एवं सदस्य:
अध्यक्ष: प्रोनाब सेन, भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद् और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) के पूर्व अध्यक्ष, को एससीओएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्यता: एससीओएस में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों सहित 10 आधिकारिक सदस्य और चार गैर-आधिकारिक सदस्य शामिल हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आदेश के अनुसार 16 सदस्यों तक का प्रावधान है।

महत्व:
आलोचनाओं को संबोधित करना: प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों द्वारा भारत की सांख्यिकीय मशीनरी की आलोचना के बीच एससीओएस का गठन महत्वपूर्ण है।
संदर्भ की शर्तें: एससीओएस को सभी सर्वेक्षण रूपरेखाओं, कार्यप्रणाली और परिणामों की समीक्षा करने, आधिकारिक आंकड़ों के लिए डेटा अंतराल की पहचान करने और उन अंतरालों को भरने के लिए रणनीति बनाने का काम सौंपा गया है।
प्रशासनिक सांख्यिकी का उपयोग: डेटा परिणामों में सुधार के लिए प्रशासनिक सांख्यिकी का उपयोग करना अनिवार्य है।
सर्वेक्षण परिणामों को मंजूरी: पैनल सर्वेक्षण परिणामों को अंतिम रूप देता है,जबकि प्रकाशन को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार एनएससी के पास रहता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI):

निर्माण: 1999 में सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के माध्यम से एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में गठित किया गया।
विंग: इसमें सांख्यिकी विंग (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय - एनएसओ) और कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग शामिल हैं।

- **सांख्यिकी विंग**: इसमें केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), कंप्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) शामिल हैं।
- **कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग**:इसे बीस सूत्री कार्यक्रम, बुनियादी ढांचे की निगरानी, परियोजना निगरानी, और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में विभाजित किया गया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग:यह सरकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है , जो सांख्यिकीय पद्धतियों और मानकों के विकास और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।
भारतीय सांख्यिकी संस्थान: यह सांख्यिकी में अनुसंधान और शिक्षण के लिए समर्पित राष्ट्रीय महत्व का एक स्वायत्त संस्थान है , जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया है।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

18 July 2023

NEWS IN BETWEEN THE LINES

इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग

संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे।

इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग क्या है?

इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एक आधुनिक हवाईअड्डा टर्मिनल को संदर्भित करता है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिचालनों को एक छत के नीचे समेकित करता है।

कनेक्टिविटी को बढ़ावा: नया टर्मिनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, इसकी लागत लगभग 710 करोड़ रुपये है।

अद्वितीय वास्तुकला: एक शंख के आकार का टर्मिनल, समुद्र और द्वीपों का प्रतीक है, जो एक विशिष्ट विशेषता दर्शाता है।

संधारणीय सुविधाएँ: इसमें डबल इंसुलेटेड छत, रोशनदान, एलईडी लाइटिंग, वर्षा जल संग्रहण, सीवेज उपचार संयंत्र और 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र जैसे संधारणीय उपाय शामिल हैं।

पर्यटन को बढ़ावा: पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है।

रोजगार के अवसर: नया टर्मिनल स्थानीय रोजगार पैदा करता है और क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान देता है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक

संदर्भ: हाल ही में नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया, जिसमें 2015-16 और 2019-21 के बीच देश की गरीबी दर में 24.85% से 14.96% की गिरावट देखी गई है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है?

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) एक उपकरण है जिसका उपयोग भारत में आय-आधारित संकेतकों से परे गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। यह गरीबी की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे कई आयामों का आकलन करता है।

गरीबी में गिरावट: नीति आयोग द्वारा "राष्ट्रीय एमपीआई, एक प्रगति समीक्षा, 2023" के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी में 9.89 प्रतिशत अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। यह 2015-16 में 24.85% से घटकर 2019-2021 में 14.96% हो गई है।

मूल्यांकित आयाम: सूचकांक तीन मूलभूत आयामों का मूल्यांकन करता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। यह पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, बिजली तक पहुंच, स्वच्छता और आवास की गुणवत्ता जैसे संकेतकों का विश्लेषण करता है।

क्षेत्रीय असमानताएँ: एमपीआई गरीबी में क्षेत्रीय असमानताओं की पहचान करने में मदद करता है, जिससे सबसे कमजोर समुदायों के उत्थान के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप सक्षम होते हैं।

भूमि सम्मान पुरस्कार

संदर्भ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भूमि रिकॉर्ड के 100% डिजिटलीकरण को प्राप्त करने के लिए 68 जिला कलेक्टरों और नौ राज्य सचिवों को भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया।

भूमि सम्मान पुरस्कार क्या है?

भूमि सम्मान पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड के 100% डिजिटलीकरण को प्राप्त करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अधिकारियों और व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है।

उद्देश्य:

शासन में भूमिका: भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण शासन प्रणालियों को आधुनिक बनाने, नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करने और भूमि लेनदेन में धोखाधड़ी प्रथाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नागरिकों के लिए निहितार्थ: यह पुरस्कार उन प्रयासों को मान्यता देता है जो भूमि से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करके, विवादों को कम करके और समय पर एवं सटीक संपत्ति दस्तावेज़ीकरण की सुविधा प्रदान करके नागरिकों को सीधे लाभान्वित करते हैं।

सरकारी पहल: भूमि सम्मान पुरस्कार केंद्र सरकार की एक पहल है, जो भूमि प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर देती है।

नमदा शिल्प

संदर्भ: हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के सदियों पुराने शिल्प, जिसे 'नमदा' के नाम से जाना जाता है, के पुनरुद्धार के लिए आग्रह किया है।

नमदा शिल्प क्या है?

नमदा शिल्प भारत में कश्मीर क्षेत्र से उत्पन्न हस्तशिल्प का एक पारंपरिक रूप है। इसमें फेल्टिंग तकनीक का उपयोग करके गलीचे, कालीन, कंबल और सजावटी टुकड़ों सहित फेल्टेड ऊनी वस्त्रों का निर्माण शामिल है।

तकनीक: इसमें कपड़ा बनाने के लिए गर्मी, नमी और दबाव का उपयोग करके ऊन को फेल्ट करना शामिल है।

उत्पाद: नमदा शिल्प गलीचे, कालीन, कंबल और सजावटी सामान जैसी वस्तुओं का उत्पादन करता है।

कलात्मक महत्व: नमदा उत्पाद स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और उनकी अनूठी एवं उत्तम कलात्मकता के लिए विश्व स्तर पर कला प्रेमियों द्वारा प्रशंसा की जाती है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

	आर्थिक महत्व: नमदा शिल्प को बढ़ावा देने से स्थानीय कारीगरों को आर्थिक अवसर मिल सकते हैं और उनकी आजीविका में सुधार हो सकता है।
गम्बूसिया मछली 	**संदर्भ:** हाल ही में, आंध्र प्रदेश सरकार ने मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए 10 मिलियन गम्बूसिया मछली को जल प्रणाली में छोड़ा है। **जैविक नियंत्रण:** गम्बूसिया मछली, जिसे मॉस्किटोफ़िश के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंट के रूप में किया जाता है। **मलेरिया और डेंगू:** इस पहल का उद्देश्य राज्य में मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों से निपटना है। **प्रजनन क्षमता:** एक मादा गंबूसिया अपने जीवनकाल के दौरान 900 से 1,200 संतानें पैदा कर सकती है, जिससे उच्च प्रजनन क्षमता और विभिन्न वातावरणों में अनुकूलन क्षमता होती है। **आक्रामक प्रजातियाँ:** गंबूसिया को प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा 100 सबसे खराब आक्रामक विदेशी प्रजातियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। **पारिस्थितिक प्रभाव:** गंबूसिया ने भारत में नैनीताल झील के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को प्रभावित किया, जिससे स्थानीय जैव विविधता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएँ उजागर हुईं। **डब्ल्यूएचओ की चेतावनी:** विश्व स्वास्थ्य संगठन गंबूसिया जैसी विदेशी मछली प्रजातियों को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ने के प्रति आगाह करता है, क्योंकि वे स्थानीय प्रजातियों और जलीय जानवरों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। **चिंताएँ:** आक्रामक विदेशी गंबूसिया प्रजाति से आंध्र प्रदेश में स्वदेशी मीठे पानी की प्रजातियों को संभावित नुकसान की चिंता बढ़ गई है।
एंडोमेट्रियोसिस 	**संदर्भ:** हाल ही में, एंडोमेट्रियोसिस, एक प्रजनन रोग जो दुनिया भर में 10 में से 1 महिला को प्रभावित करता है, ने ध्यान आकर्षित किया है। **एंडोमेट्रियोसिस क्या है?** एंडोमेट्रियोसिस एक दर्दनाक पुरानी बीमारी है जिसमें गर्भाशय की परत जैसा दिखने वाला ऊतक गर्भाशय के बाहर बढ़ता है। यह वैश्विक स्तर पर प्रजनन आयु की लगभग 10% (190 मिलियन) महिलाओं को प्रभावित करता है। **लक्षण:** सामान्य लक्षणों में गंभीर पेल्विक दर्द, दर्दनाक माहवारी, पेशाब, संभोग और मल त्याग के दौरान दर्द, साथ ही थकान और संभावित बांझपन शामिल हैं। **आयु सीमा:** एंडोमेट्रियोसिस किसी व्यक्ति के पहले मासिक धर्म से शुरू हो सकता है और रजोनिवृत्ति तक जारी रह सकता है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं। **ऐतिहासिक खोज:** एंडोमेट्रियोसिस की पहचान पहली बार 1860 में हुई थी, लेकिन इसके पहले बायोमार्कर 150 साल बाद खोजे गए, जो इसके निदान की जटिलता को दर्शाता है। **कारण:** एंडोमेट्रियोसिस का सटीक कारण अज्ञात है। यह दुनिया भर में विभिन्न नृजातीय मूल और सामाजिक स्थितियों की महिलाओं को प्रभावित करता है।
बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य 	**संदर्भ:** हाल ही में, असम के बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य में एक महिला की गोली मारकर दुखद हत्या कर दी गई और तीन वन रक्षकों सहित छह अन्य घायल हो गए। **स्थान:** बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है। **भौगोलिक विशेषताएं:** अभयारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और लगभग 44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। **पक्षीविविधता:** अभयारण्य विशेष रूप से अपनी महत्वपूर्ण पक्षी आबादी के लिए पहचाना जाता है, यहाँ कई प्रवासी प्रजातियों सहित पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। **स्तनधारी:** बुरा चापोरी विभिन्न स्तनधारी प्रजातियों का घर है, जिनमें गंगा डॉल्फिन, जलीय भैंस, कैप्ड लंगूर, बंगाल लोमड़ी और हिरण की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। **वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र:** अभयारण्य में वेटलैंड्स, नदी चैनल, सैंडबार और घास के मैदान शामिल हैं, जो वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सहायता और संसाधन प्रदान करते हैं। **संरक्षण के प्रयास:** बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित है, और इसकी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए संरक्षण पहल की जा रही है।

बिम्सटेक

संदर्भ: हाल ही में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्सटेक के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया।

स्थापना: बिम्सटेक की स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। यह मूल रूप से BIST-EC (बांग्लादेश-भारत-श्रीलंका-थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के रूप में जाना जाता है, बाद में 1997 में म्यांमार के शामिल होने तथा 2004 में भूटान और नेपाल के शामिल होने के साथ बिम्सटेक बन गया।

फोकस क्षेत्र: शुरुआत में, बिम्सटेक का सहयोग 1997 में छह क्षेत्रों पर केंद्रित था, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन शामिल थे।

क्षेत्रीय सहयोग: बिम्सटेक का लक्ष्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अपने सदस्य देशों के बीच बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

भारत की भागीदारी: एक प्रमुख सदस्य के रूप में, भारत क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्सटेक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

समाचार में स्थान

केर्च ब्रिज

संदर्भ: हाल ही में रूस को कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले केर्च ब्रिज पर दो विस्फोटों से हमला किया गया था।

भौगोलिक स्थिति: केर्च ब्रिज केर्च क्षेत्र में स्थित है, जो रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ता है। यह केर्च जलडमरूमध्य तक फैला है, जो काला सागर और आज़ोव सागर को अलग करता है।

महत्व: यह एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है जो मुख्य भूमि रूस और क्रीमिया के बीच सीधी सड़क और रेल लिंक प्रदान करने, कनेक्टिविटी और परिवहन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

लंबाई: यह पुल केर्च जलडमरूमध्य में लगभग 19 किलोमीटर (11.8 मील) तक फैला है, जो इसे यूरोप के सबसे लंबे पुलों में से एक बनाता है।

उद्घाटन: पुल को आधिकारिक तौर पर मई 2018 में सड़क यातायात के लिए खोला गया था, और रेल खंड का उद्घाटन दिसंबर 2019 में किया गया था।

राजनीतिक विवाद: केर्च ब्रिज का निर्माण और संचालन क्रीमिया की विवादित स्थिति के कारण अत्यधिक विवादास्पद रहा है, जिसे 2014 में रूस द्वारा कब्जा कर लिया गया था।

महत्व: यह क्रीमिया को ईंधन, भोजन, हथियार और अन्य उत्पादों की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करता है, जहां सेवस्तोपोल बंदरगाह रूस के काला सागर बेड़े के ऐतिहासिक घरेलू आधार के रूप में कार्य करता है।